आकाशवाणी शिमला
16.01.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- **केन्द्रीय कर्मचारियों व पैंशनभोगियों के लिए केन्द्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की।**
- **मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–बीबीएनडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी से बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा बढ़ावा।**
- **उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार–ऊना ज़िला में खनन पर एक साल के लिए रहेगा प्रतिबंध।**
- **प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट–कल से 21 जनवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना।**

वेतन आयोग

केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। सरकार के इस फैसले से रक्षा कर्मियों सहित करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा लगभग 65 लाख पैंशनर भी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ विकास प्राधिकरण बीबीएनडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी–2025 आरम्भ की है। इसका मुख्य उद्देश्य सोलन जिला के बीबीएन क्षेत्र में संगठित और सतत् विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के माध्यम से भूमि मालिकों के सहयोग से भूमि को पूल व विकसित करके क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं और नियोजित लेआउट की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, मिश्रित उपयोग और बुनियादी ढांचे के उन क्षेत्रों में बीबीएनडीए विकास परियोजना को बढ़ावा देगा जिन्हें अनुमोदित विकास योजना के तहत शहरीकरण क्षेत्रों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति बीबीएन क्षेत्र में विकास को सुव्यवस्थित करने, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने से क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

भेंट

राज्य सरकार द्वारा 13 दिवसीय भ्रमण पर भेजे गए 22 बच्चों ने वापिस लौटने के बाद आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। इस दौरान इन बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ शैक्षणिक और मनोरंजक यात्रा के बारे में अपने अनुभव साझा किए। यात्रा पर गए बच्चों न मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक स्मारकों को देखने का मौका भी मिला। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने

राज्य के अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन ए.आइ.आर. मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डी.डी. न्यूज, पी.एम.ओ. और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा।

स्टार्ट–अप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक लाख 54 हजार से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इसके अलावा नेतृत्व स्तर पर महिलाओं के 48 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के साथ इन स्टार्टअप ने 17 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। हिमाचल प्रदेश में भी स्टार्टअप से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन और खनिजों के परिवहन की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर चौकियां स्थापित की गई हैं। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि नालागढ़, ऊना, नूरपुर और पावंटा साहिब जैसे क्षेत्र अवैध खनन के लिए अत्याधिक संवेदनशील है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ऊना ज़िला में खनन पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

मौसम

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से रूक रूक कर हल्की बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं–कहीं वर्षा हुई है। ताजा बर्फबारी व वर्षा से तापमान में 4 से 5 डिग्री सैल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। किन्नौर ज़िला में बर्फबारी के कारण 90 सम्पर्क सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरूद्ध हो गए हैं। उधर कुल्लू ज़िले में बंजार–आनी सड़क मार्ग जलोड़ी जोत पर ताजा हिमपात के चलते वाहनों के आवाजाही के लिए बंद है। वहीं चंबा ज़िला में भी चंबा–पठानकोट वाया जोत मार्ग बर्फबारी के कारण यातायात के लिए अवरूद्ध हो गया है। मौसम विज्ञान केन्द्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में बारिश व बर्फबारी का क्रम आज देर शाम तक जारी रहेगा जबकि कल से 21 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है।